

# मुंबई तरंग

www.mumbaitarang.com

संपादक : दिलीप नानजीभाई पटेल

उप संपादक: किरिट अमृतलाल चावड़ा ✦ वर्ष-03 ✦ अंक-14 ✦ मुंबई ✦ रविवार 27 मार्च से 02 अप्रैल 2022 ✦ पृष्ठ-8 ✦ ₹4/-

**पेज 3**

**परमबीर सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपी मामले की जांच**

**पेज 5**

**पंजाब में अब 'वन MLA-वन पेंशन': CM भगतवंत मान ने कहा- चाहे कितनी बार चुनाव जीता हो, पेंशन एक टर्म की मिलेगी**

**पेज 7**

**फिर मसीहा बने सोनू सूद, पेटेंट ने मांगी मदद तो अभिनेता बोले- अब स्कूल से नहीं आया कॉल**

**पेज 8**

**मोदी Vs केजरीवाल: भाजपा के यूपी मॉडल और आप के पंजाब मॉडल में होगी लड़ाई, कौन जीतेगा जनता का दिल?**

## सत्ता हथियाने के लिए मुझे जेल में डालना चाहती है BJP

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कार्यवाही का सामना करने के तीन दिन बाद, ठाकरे ने बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोपों और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार, उनके नेता और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर भी सवाल उठाया। ठाकरे ने कहा, 'मैं इन हथकंडों से नहीं डरता। अगर आप मुझे सत्ता में आने के लिए जेल में डालना चाहते हैं, तो डाल दें लेकिन सत्ता हथियाने के लिए इस तरह के दुराचारी व्यवहार में शामिल न हों। हमें या हमारे परिवार के सदस्यों को परेशान न करें। हमने कभी आपके परिवार के सदस्य को परेशान नहीं किया।' कोविड -19



→ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर किया प्रहार  
→ मैं इन हथकंडों से नहीं डरता, मेरे परिवार की मानहानि ना करें: ठाकरे

महामारी, मंत्री नवाब मलिक और अन्य के प्रकरण के दौरान बृहन्मुंबई नगर निगम में विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों के अपने तीखे जवाब में, ठाकरे ने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन के 'मुंबई मॉडल' का विश्व स्तर पर स्वागत किया गया है और विपक्ष का स्वागत है

कि वह किसी भी चूक को इंगित करें, जिसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी से निराधार आरोप लगाना बंद करने का आह्वान किया। बराक ओबामा के बहाने प्रधानमंत्री से पूछा सवाल यह पूछे जाने पर कि क्या ईडी बीजेपी की 'नौकर' बन गई है, खासकर विशेष रूप से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और

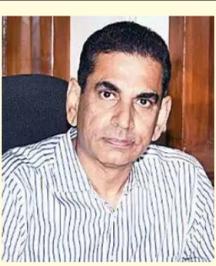
बाद में मलिक की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ने मलिक और एमवीए को सामान्य रूप से माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ने और चुनावों में भगोड़े के नाम का उपयोग करने के लिए विपक्ष पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने याद किया कि कैसे राज्य के पूर्व गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने दाऊद को वापस

### मेरे परिवार को बदनाम न करें: उद्धव ठाकरे

लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना पूछा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने कमांडो को पाकिस्तान भेजकर हिम्मत दिखाई।

## विदेश में बनाई करोड़ों की संपत्ति? MVA के मंत्रियों के बाद बीजेपी के निशाने पर बीएमसी कमिश्नर

मुंबई: महाविकास अघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र बीजेपी के बीच चल रही अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, श्रीधर पाटणकर और यशवंत जाधव के बाद अब बीजेपी ने देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने आरोप लगाया है कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने विदेशों में काफी संपत्ति जमा की है। वे आने वाले दिनों में इससे संबंधित सबूतों वाली फाइल जांच एजेंसी को सौंपेंगे। आपको बता दें कि मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीएमसी कमिश्नर को 10 मार्च को नोटिस भेजा था। मोहित कंबोज ने कहा कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के आंच के तारे इकबाल सिंह चहल बीते 2 साल से



सुरिखियों में हैं। इस बार वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस की वजह से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मोहित कंबोज ने कहा कि आयकर विभाग से मेरा यह सवाल है कि सिर्फ नेताओं की ही जांच क्यों की जाती है? नौकरशाहों और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जानी चाहिए। कंबोज ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के लिए यह भी जानना जरूरी है कि

यशवंत जाधव के भ्रष्टाचार में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल किस हद तक शामिल थे। मोहित कंबोज ने कहा कि बीजेपी विधायक अमित साठम फिलहाल बीएमसी के भ्रष्टाचार पर एक किताब आने वाले 15 दिनों में प्रकाशित करने जा रहे हैं। जो नगरपालिका में दो साल के दौरान हुए भ्रष्टाचार का लेखा-जोखा होगा। कंबोज ने कहा कि इस जांच को सिर्फ यशवंत जाधव तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें शामिल सभी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए ताकि उनका भ्रष्टाचार बाहर आ सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके। मोहित कंबोज ने कहा, 'हम यह मांग करते हैं कि मिसिजों पर लगाए गए अनेक लाउडस्पीकर को हटवाया जाए। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया था।

## अब समंदर का मीठा पानी पीयेंगे मुंबईकर साल 2025 से होगी शुरुआत



की समस्या दूर कर सकेंगे। ग्लोबल टेंडर से मिलेगा फायदा इस प्रोजेक्ट के लिए बीएमसी ने इससे पहले मई 2022 में ग्लोबल टेंडर निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के कारण इसमें देरी हुई। अब ग्लोबल टेंडर सितंबर तक निकलने की उम्मीद है। ग्लोबल टेंडर निकालने से बीएमसी के पास चुनने के कई विकल्प मौजूद होंगे। इससे क्वॉलिटी पर फोकस करने का मौका मिलेगा। मनोरी प्रोजेक्ट के लिए बीएमसी, एमटीडीसी से 12 हेक्टेयर जमीन लेगी। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने पर पहले चरण में प्रतिदिन मुंबई को 200 एमएलडी पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में मुंबई को 400 एमएलडी पानी की प्रतिदिन आपूर्ति होगी। इस प्रोजेक्ट पर बीएमसी 3520 करोड़ रुपये खर्च करेगी। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इस वजह से मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

मुंबई: मालाड के मनोरी में समुद्र के पानी को मीठा करने की योजना पर बीएमसी(BMC) आगे बढ़ रही है। बीएमसी को उम्मीद है कि दिसंबर, 2022 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल विशेष ध्यान दे रहे हैं। बीएमसी की कोशिश है कि मनोरी प्रोजेक्ट से वर्ष 2025 तक मुंबईकरों को पानी मिलने लगे। बीएमसी वॉटर डिपार्टमेंट के चीफ इंजिनियर (प्रोजेक्ट) वसंत गायकवाड ने बताया कि डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के

लिए एमटीडीसी से जगह अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू है। इन सब कार्यों को पूरा करने में अगस्त-सितंबर तक का समय लग सकता है। उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। गायकवाड ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में तीन साल का समय लग सकता है। हमारी कोशिश है कि वर्ष 2025 से मुंबईकरों को समुद्र का मीठा पानी पीने के लिए मिलने लगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बजट भाषण के दौरान भी इस प्रोजेक्ट की खासियत बताई थी। उन्होंने कहा था कि समुद्र से पानी मीठा करने का प्रोजेक्ट सफल होने के बाद मुंबई में काफी हद तक हम पानी

## मुंबई के KEM अस्पताल में भी दवाओं की किल्लत स्लाइन, मरहम पट्टी तक बाहर से खरीदने की नौबत



मुंबई: राज्य सरकार के सबसे बड़े अस्पताल जेजे(JJ Hospital) में दवाई जा रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन दवाई के अभाव के लिए केंद्रीय खरीदारी को निमंत्रित कर रहा है। केईएम अस्पताल(KEM Hospital) में भी दवाई की किल्लत का मामला सामने आया है। यहां आनेवाले मरीजों को इन दिनों इलाज के लिए लगनेवाली सभी

दवाइयां बाहर निजी मेडिकल से खरीदकर लानी पड़ रही हैं। इस वॉर्ड में भर्ती बबन सावंत के भतीजे मुकेश जाधव ने बताया कि अंबलाथ से सुबह 3 बजे वे अपने चाचा बबन सावंत को लकवा मारने की वजह से केईएम अस्पताल ले आए। सबसे से अभी तक उनके इलाज में लगनेवाली छोटी से छोटी दवाइयां तक बाहर से मंगाई जा रही हैं। एक अन्य मरीज लक्ष्मण साबले के बेटे हनुमंत साबले ने बताया कि उनके पिता टीबी मरीज हैं। वे अभी न ही कुछ कह पा रहे हैं और न ही कुछ खा पा रहे हैं। इनके लिए लगने वाली स्लाइन तक बाहर से मंगाई जा रही है।

दिया। हालांकि अस्पताल के ही एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि दवा और सर्जिकल सामानों की किल्लत को दूर करने के लिए पिछले दो महीनों से लोकल स्तर पर अस्पताल प्रशासन दवा खरीद रहा है। अस्पताल की डीन को अपने स्तर पर करीब 10 लाख रुपये और विभाग के प्रमुख डॉक्टर को करीब 3 लाख रुपये तक की दवाई खरीदने का अधिकार है और इसी अधिकार का इस्तेमाल दवाई खरीदने के लिए किया जा रहा है।

**दो वर्ष से बना नहीं है दवाई का शेड्यूल**  
बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीते दो वर्षों से यह दिक्कत हो रही है। जिस वजह से बीएमसी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत हो रही है। सिर्फ प्रमुख अस्पतालों में ही नहीं छोटे-छोटे दवाखानों, प्रसूति गृहों में भी दवाइयों

का अभाव है। इस कमी को पूरा करने के लिए लोकल स्तर पर दवाई खरीदारी की जा रही है। दवाखानों और प्रसूति गृहों में लोकल स्तर पर तीन से 5 हजार रुपये तक दवाई खरीदी जा रही है।  
**क्या कहते हैं अधिकारी**  
केंद्रीय खरीदारी विभाग के उपायुक्त रमाकांत बिरादर ने बताया कि अस्पतालों में दवाई की किल्लत का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि दवाई की कमी पर लोकल स्तर पर खरीदारी करने का अधिकार अस्पताल के डीन और विभाग के प्रमुखों को दिया गया है। उनके विभाग की ओर से शेड्यूल समय पर ही दवा दिया जाता है। विभाग का काम दवाई खरीदारी के लिए एजेंसी नियुक्त करना है। एजेंसी नियुक्ति के बाद अस्पताल प्रशासन को बता दिया जाता है कि संबंधित एजेंसी और कंपनी से उन्हें दवा लेनी है।

## लगातार पांचवें दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, नितिन गडकरी ने बताई रोज ईंधन के दाम बढ़ने की वजह

चार महीने तक ईंधन की कीमतों स्थिर रहने के बाद मंगलवार को कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी होनी शुरू हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस लगातार बढ़ती हुई कीमतों की वजह क्या है? यह सवाल केंद्रीय सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी से पूछा गया, नितिन गडकरी ने इसका जवाब दिया।

ईंधन की दर दिन-ब-दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लगातार पांचवें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन पांच दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम चार बार बढ़ाए गए हैं। शनिवार (26 मार्च) को भी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी की है। शनिवार को पेट्रोल-डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह पिछले पांच दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमत 112.51 रुपये प्रति लीटर से बढ़ कर 113.35 रुपये प्रति लीटर हो गई। इसी तरह डीजल की कीमत 96.70 रुपये से बढ़ कर 97.55 रुपये प्रति लीटर हो गया। इस तरह दिल्ली की बात छोड़ दें तो लगभग सभी महानगरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये को क्रॉस कर चुका है। दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल की



कीमत 98.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दर 89.87 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस बेतहाशा होती हुई बढ़ोत्तरी की वजह से आम आदमी की जेब पर काफी बोझ बढ़ा है। चार महीने तक ईंधन की कीमतें स्थिर रहने के बाद मंगलवार को कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी होनी शुरू हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस लगातार बढ़ती हुई कीमतों की वजह क्या है? यह सवाल केंद्रीय सड़क परिवहन और

बढ़ने का रेशन होगा कम, हर पांच किलोमीटर पर बन रहे हैं चार्जिंग स्टेशन 19 मार्च 2022 तक देश में 10 लाख 60 हजार 707 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह जानकारी सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दी। एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा, 'ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी के मुताबिक 21 मार्च 2022 तक देश में 1742 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हो चुके हैं। देश के अहम महानगरों पर 5 किलोमीटर के अंतर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम किया जा रहा है।' जब ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे तो बहुत हद तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी का असर कम हो जाएगा। यह वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता दिखाई जा रही है। सरकार की ओर से इसे बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है।

## मुंबई वसूली मामले में घिरे कटर अधिकारी सौरभ त्रिपाठी की सफाई, कहा- सीनियर के आदेशों पर फंसाया गया

महाराष्ट्र के मुंबई में अंगड़िया व्यापारियों से कथित वसूली मामले में महाराष्ट्र के डी.पी.एस. अधिकारी सौरभ त्रिपाठी पर लगे वसूली के आरोपों के बाद उन पर तलवार लटकने लगी। वहीं, DCP सौरभ त्रिपाठी ने दावा किया है कि उन्हें अपने सीनियर के दबाव के कारण अंगड़िया फिरीती मामले में फंसाया गया है। त्रिपाठी के वकील ने उस रिपोर्ट की कॉपी की भी मांग की जिस पर सौरभ त्रिपाठी पर अचानक आरोप लगाया गया था। हालांकि, जांच शुरूआती चरण में है और याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इस दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि भगोड़े घोषित किए गए सस्पेंड DCP सौरभ त्रिपाठी ने मुंबई सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत मांगी है। जहां पर बीते गुरुवार को जस्टिस आर.एम. सदरानी के समक्ष सुनवाई हुई। ऐसे में अनिकेत निकम अपने मुवकिल सौरभ त्रिपाठी के लिए बहस कर रहे हैं और सुनवाई शुरूवार को भी जारी रहेगी। दरअसल, वकील अनिकेत निकम ने कोर्ट में दावा किया है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड ओम वंगटे है। वह है जिसने इन अंगड़ियों को धमकाया और उनसे जबरन वसूली की। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि वंगटे, कदम और जामदाडे इन पुलिस अधिकारियों से की गई पूछताछ में सौरभ त्रिपाठी के नाम का जिक्र कभी नहीं आया था, जब वे पुलिस हिरासत में थे या मामला दर्ज होने से पहले भी नाम नहीं आया था। जिस दिन इन्वेन्युअरिडिग्रासमेंत में भेजा गया, तब अचानक DCP सौरभ त्रिपाठी का नाम



कैसे आ गया ? साथ ही त्रिपाठी पर इस मामले में लूट का आरोप लगाने वाली धाराएं पूरी तरह से अवेध हैं। सौरभ त्रिपाठी ने भी इस मामले में अपना शुरूआती जवाब दर्ज किया है। जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।  
**सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया**  
वहीं, बीते साल दिसंबर 2021 में, अंगड़िया एसोसिएशन ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से संपर्क किया था, जिसमें उसने DCP सौरभ त्रिपाठी पर आरोपों को चालू रखने के लिए DCP जोन 2 से हर महीने 10 लाख रुपये की फिरीती मांगने का आरोप लगाया। इस पर कमिश्नर ने आरोपों की जांच के लिए साउथ डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर दिलीप सावंत को नियुक्त किया है। हालांकि, इस

मामले में एल.टी. मार्ग थाना निरीक्षक ओम वांगटे, एपीआई नितिन कदम और पीएसआई समाधान जामदाडे से पूछताछ की गई। उस समय, वांगटे और अन्य 2 अधिकारियों पर एल.टी. मार्ग थाने में फिरीती का मामला दर्ज किया गया है।  
**मुंबई क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट ने DCP त्रिपाठी को किया भगोड़ा घोषित**  
गौरतलब है कि गिरफ्तार अधिकारियों पर दिसंबर में अंगड़िया एसोसिएशन से 18 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच गबन करने का आरोप लगाया गया है, उनके खिलाफ आरोप दर्ज करने या उनकी अवेध गतिविधियों के बारे में आवक विभाग को सूचित करने की धमकी दी गई है। इस पर त्रिपाठी के खिलाफ आगे की जांच में फिरीती का मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने राज्य के गृह विभाग को पत्र भेजकर प्रशासनिक कार्यवाही के तौर पर डीसीपी को विभागीय जांच के लिए सस्पेंड करने की मांग की थी। त्रिपाठी के खिलाफ 18 फरवरी को मामला दर्ज किया गया है और वह तब से सेवा में अनुपस्थित हैं। इसलिए मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंस्टीट्यूट यूनिट (CIU) ने त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह देखते हुए, सीएम ने अंततः 20 मार्च को डीसीपी सौरभ त्रिपाठी के सस्पेंशन पर हस्ताक्षर किए, जानिए कौन हैं सौरभ त्रिपाठी?  
बता दें कि महाराष्ट्र के डी.पी.एस. अधिकारी सौरभ त्रिपाठी साल 2010 के डी.पी.एस. अधिकारी, जिनके पास MBBS और एमडी (त्वचविज्ञान) की डिग्री है,





## राजनीति में हिंसा रुके, ममता बनर्जी के सामने दोहरी चुनौती

बयानबाजी हुई, वह वाकई मिराशाजनक है। मुख्यमंत्री ने घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए भी इसके पीछे राज्य को बदनाम करने की संभावित साजिश का जिक्र कर दिया। ऐसे बयान उन आशंकाओं को मजबूती देते हैं कि हिंसा यहां की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा काफी पहले से बनी हुई है। तीन दशकों से ऊपर के लेफ्ट शासन के दौरान यहां राजनीतिक और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में सीपीएम कार्यकर्ताओं का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। अपने लिए स्पेस बनाने की विरोधी पार्टियों की कोशिशों से उस दौरान प्रायः हिंसक प्रयास भी उसकी तरफ से होता नहीं दिखता। नतीजा यह कि जिस 'सिंडिकेट कल्चर' को कोसते हुए तृणमूल सत्ता में आई, वह और व्यापक हुआ। इसी का नतीजा है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद जब तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की हत्या होती है तो उसके शोक संतप्त समर्थक भी ईसाफ के लिए पुलिस और प्रशासन का मुंह देखने के बजाय खुद कानून हाथ में लेकर संदिग्धों को तत्काल सजा देने का अभियान शुरू कर देते हैं। ममता बनर्जी न केवल तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता और राज्य की मुख्यमंत्री हैं बल्कि हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पराजित करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का संभावित साझा चेहरा भी मानी जा रही हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दुस्त रखने के साथ ही हिंसा की संस्कृति खत्म कर यहां लोकतांत्रिक राजनीति का दायरा बढ़ाने की चुनौती भी उनके सामने है। इस दिशा में कारगर प्रयासों से ही राष्ट्रीय राजनीति में विकल्प के उनके दावे को प्रामाणिकता मिलेगी।



कहीं जांच प्रक्रिया को खास दिशा देने की कोई मंशा तो काम नहीं कर रही। बहरहाल, बीरभूम की घटना पश्चिम बंगाल के लिए न तो नई है और न ही आश्चर्यजनक। संगठित तरीकों से ही निपटा जाता था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के वर्चस्व को तो खत्म किया, लेकिन राजनीति की इस शैली को बदलने का कोई खास

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की हत्या के बाद जिस तरह से आठ लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इसमें केंद्र, राज्य सरकार की हर तरह से मदद करने को तैयार है। इसके साथ मोदी ने राज्य के लोगों से ऐसी हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने वाले लोगों को कभी माफ न करने की अपील की। प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाएं तो ऐसी घटना के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से ऐसे ही संयत और गंभीर रुख की अपेक्षा की जाती है। राज्य में इस घटना को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनकड़ आमने-सामने नजर आए और दोनों में तीखी

## 12वीं के नंबर का अब नहीं रहेगा कोई रेल, CUET के आधार पर मिलेगा ग्रेजुएशन में एडमिशन

यूजीसी ने देश की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उनसे जुड़े कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) को अनिवार्य बनाकर शिक्षा में सुधार की एक बड़ी पहल की है। इन तमाम यूजी कोर्स में एडमिशन के दौरान अब 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हासिल नंबरों की कोई भूमिका नहीं होगी। यूजीसी ने साफ किया है कि यूनिवर्सिटी चाहें तो 12वीं के नंबरों को विभिन्न कोर्सों के एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने की पात्रता का आधार बना सकती हैं, लेकिन एडमिशन पूरी तरह से सीयूईटी में हासिल नंबरों के ही आधार पर होगा। इस व्यवस्था का पहला स्वागत योग्य परिणाम यह होगा कि विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन की अतार्किक ढंग से ऊंची कटऑफ लिस्ट अतीत की बात बन जाएगी। ऊंची कटऑफ की समस्या दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में खास तौर पर देखी जाती है। कॉलेजों की ऊंची कटऑफ लाइन 2021 में भी रेकॉर्ड तोड़ती नजर आई, जबकि उस दौरान

कोरोना महामारी से उपजे हालात के चलते स्कूल ज्यादातर बंद ही रहे। डीयू के सात कॉलेजों ने दस कोर्सों के लिए इस साल भी पहली कटऑफ लिस्ट 100 फीसदी नंबर की घोषित की थी। विभिन्न राज्यों के 12वीं की मार्कशीट को सब कुछ मानने वाली व्यवस्था की जगह उसे कुछ नहीं मानने वाली व्यवस्था लागू की जा रही है, उससे शुरू में कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। 12वीं के बहुत से स्टूडेंट्स इसे लेकर

आशंकित भी हैं। ध्यान रहे कि इसी साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को दो अलग-अलग टर्मों में बांटा गया। यही नहीं, पहले टर्म के नंबर तब आए जब दूसरे टर्म की परीक्षाएं सिर पर आ चुकी थीं। इसके अलावा सीयूईटी परीक्षा के लिए आवेदन



अप्रैल में मंगवाए जाएंगे और परीक्षा जुलाई में आयोजित की जानी है। जाहिर है, तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा। कम से कम इस बेच के स्टूडेंट्स के लिए यह सब खासा तनाव पैदा करने वाला साबित हो सकता है। बावजूद इसके, पुरानी व्यवस्था का खाम्ता जरूरी था। अब नई व्यवस्था से पैदा होने वाली शुरुआती असुविधाओं के हल खोजे जाएं और यह भी याद रखा जाए कि नई व्यवस्था भी सभी समस्याओं का हल नहीं है। इसके जरिए देश भर के स्टूडेंट्स की क्वॉलिटी एजुकेशन तक पहुंच को आसान बनाने की कोशिश की गई है, पर स्टूडेंट्स की संख्या और सीटों के अनुपात को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या प्रवेश के इच्छुक स्टूडेंट्स के मुकाबले कम ही पड़ने वाली है। यह एक बड़ी और जटिल समस्या है। जाहिर है, इसके लिए बड़े सुधार की जरूरत है।



शिक्षा बोर्डों की अलग-अलग मूल्यांकन पद्धतियों के मद्देनजर देश के अलग-अलग हिस्सों के स्टूडेंट्स के लिए यह व्यवस्था असंगत साबित हो रही थी। नई व्यवस्था इस विसंगति को दूर करेगी। हालांकि एक झटके में जिस तरह से

## जा सकती है इमरान खान की सरकार, पर हौसले बुलंद हैं



अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र ही मतदान होना है, लेकिन यह भी संभव है कि उसके पहले ही इमरान अपने इस्तीफे की पेशकश कर दें। इमरान के इस्तीफे के आसार इसलिए बढ़ गए हैं कि जिस फौज के दम पर उनका तकिया था, वही अब उन्हें हवा देने लगी है। फौज से मोहभंग इमरान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीके-ईसाफ' पार्टी (पीटीआई) 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। संसद की 343 सीटों में से उसे 155 सीटें मिली थीं। लेकिन कई अन्य पार्टियों की 24 सीटें जोड़कर वह सत्तारूढ़ हो गई। इमरान की इस जीत के पीछे पाकिस्तान फौज की शै थी। भुट्टो की पीपीपी और नवाज की मुस्लिम लीग के कई सांसदों को तोड़कर फौज ने उन्हें इमरान की पार्टी का उम्मीदवार बनवा दिया था। नवाज शरीफ को अपदस्थ

करने की मांग करने के कारण इमरान पाकिस्तानी फौज के करीबी बन गए थे। लेकिन फौज और इमरान का एक-दूसरे से जल्दी ही मोहभंग हो गया। दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध कदम उठाने लगे। 2019 में जब जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया गया तो उस आदेश को इतनी देर से जारी किया गया कि वह सर्वोच्च न्यायालय और जनता में भी विवाद का विषय बन गया। अदालत के आदेश पर उसे संसद से पास करवाना पड़ा। उधर, इमरान खान के भाषण तो जोरदार होते रहे लेकिन विरोधी दलों ने उनके खिलाफ काफी बड़े-बड़े प्रदर्शन सारे देश में आयोजित कर डाले। महंगाई और प्रशासनिक सुस्ती ने इमरान सरकार की हालत खस्ता कर दी। फौज इस बात से भी नाराज थी कि इमरान ने कश्मीर के सवाल को जोर से नहीं उठाया। उन्होंने भारत के साथ दिलाई बरती। अमेरिका से भी पाकिस्तान के

रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इमरान के बीच आज तक सीधा संवाद नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी हो गया है। जनरल बाजवा का यू तो इमरान ने कार्यकाल बढ़ाकर 2022 तक कर दिया था, लेकिन बाजवा को यह बात नागवार गुजर रही थी कि इमरान उनके



तक पाकिस्तान को कठपंर में ही रखा है। उसे अब तक छह बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ एक बिलियन डॉलर मिले हैं। फौज तो पाकिस्तान की असली मालिक है, लेकिन फौज और इमरान के बीच गंभीर तनाव पैदा

था। उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रचार भी खूब मिलने लगा। उन्हें 11 वीं कोर का कमांडर बनाकर पेशावर भेज दिया गया, लेकिन उनकी जगह गुमचर विभागे के मुखिया के तौर पर जनरल नदीम अंजुम को नियुक्त करने में इमरान ने देरी करनी शुरू कर दी। जनरल बाजवा और अन्य फौजियों के कान खड़े हो गए। उनका असंतोष और अविश्वास सार्वजनिक हो गया। फिर क्या था, सारे प्रमुख विरोधी दल मिल गए और उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इमरान सरकार ने बीच-बचाव करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व सेनापति राहिल शरीफ को सऊदी अरब से इस्लामाबाद भी बुलवाया, लेकिन उसका भी कोई असर

नहीं हुआ। फौज का संदेश यही है कि इमरान खुद ही इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान के विरोधी दलों ने अपने बहुमत की जुगाड़ बिठा ली है और मियां नवाज शरीफ के छोटे

इस्लामिक देशों के सम्मेलन में उस चीन के विदेश मंत्री वांग यी को इमरान ने अपना विशेष अतिथि बनाया है, जिसने शिनच्यांग के दस लाख मुसलमान उद्गरो को यातना-शिविरो में डाल रखा है। अदालती दांव इमरान के हौसले अभी भी बुलंद मालूम पड़ रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तानी संविधान की धारा-63 ए का इस्तेमाल करके वह अपने बागी सांसदों को मतदान के पहले ही अपदस्थ करवाने की कोशिश करें। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका लगा रखी है। बस, अब अदालत ही उन्हें किसी तरह बचा सकती है। वरना पाकिस्तान के लोग यह मानकर चल रहे हैं कि इमरान के दिन लद गए हैं। लेकिन यह सवाल भी बड़ा है कि जो पाकिस्तानी फौज इमरान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वह नवाज शरीफ के भाई को कैसे बर्दाश्त करेगी?

## क्वाड को नैटो जैसा क्यों बताया चीन ने

जिस तरह के हालात यूक्रेन में बन रहे हैं, उससे कुछ समय से हिंद-प्रशांत के देश चिंतित हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश हिंद-प्रशांत को लेकर अपनी रणनीति मजबूत कर रहे थे। हो सकता है कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से पश्चिमी देशों का, खासतौर पर अमेरिका का ध्यान बंट जाए। इस इलाके में चीन की जो चुनौती उभरकर आ रही है, उससे सबका ध्यान हटकर रूस की ओर चला जाए। चीन का जो ताजा बयान आया है, उसे देखते हुए यही लगता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह की उथल-पुथल रूस और चीन की दोस्ती से बन रही थी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। परीक्षक धमकी यूक्रेन क्राइसिस से चीन भले

ही थोड़ा परेशान हो, लेकिन एक बार फिर उसने दुनिया का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वह हिंद-प्रशांत में अपनी पोजिशन को लेकर नई रणनीति बना रहा है। इसीलिए उसने फिर से यह बात कही है कि जिस तरह से नैटो एक्सपेंशन ने यूरोप में युद्ध के हालात पैदा किए हैं, उसी तरह हिंद-प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके में और उथल-पुथल बढ़ाएगा। चीन के इस बयान से इस क्षेत्र के अन्य देशों की परेशानी बढ़ेगी क्योंकि चीन की वजह से उन्हें पहले ही दिक्कत हो रही थी। चीन की वजह से इस क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बने हैं और लगता नहीं है कि उसमें कोई कमी आएगी। चीन ने इस बयान से बाइडन सरकार की उस हिंद-प्रशांत

नीति पर निशाना साधा है, जिसे इस साल फरवरी में पेश किया गया था। जिस तरह से चीन बार-बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है, वैसी ही स्थिति हिंद-प्रशांत में अमेरिका के आने से बन सकती है, यह एक तरह से धमकी है। यह धमकी वह अमेरिका और पश्चिमी देशों सहित इस इलाके में मौजूद देशों को दे रहा है। वह उन्हें संदेश दे रहा है कि वे अमेरिका या पश्चिमी देशों के करीब ना जाएं। चीन अपना दबदबा और बढ़ाना चाहता है और हिंद-प्रशांत में अमेरिका का दखल बढ़ने पर उथल-पुथल की बात कहकर वह एक तरह से लकीर खींच रहा है। पिछले कुछ समय से हिंद-प्रशांत इलाके में नए अलायंस

खासतौर पर क्वाड से परेशान है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इन देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर बातचीत चल रही है। उनके बीच सहयोग बढ़ा है। एक समय चीन मान रहा था कि क्वाड कुछ नहीं है। यह कभी बनेगा ही नहीं और बन भी गया तो यह मजबूत अलायंस नहीं होगा। उसकी यह बात गलत निकली। इसे लेकर 2021 में बाइडन सरकार ने खास पहल की। उसने क्वाड में जान डालने का प्रयास किया। बाकी के तीन अन्य सदस्य देशों ने भी इस पर राजनयिक स्तर पर काफी काम किया है। उन्होंने एक अजेंडा भी बनाया है। यह अजेंडा दूसरे देशों के लिए काफी लुभावना है क्योंकि यह सिर्फ चीन को ही

टारगेट नहीं करता। इसमें कहा गया है कि हिंद-प्रशांत की जो भी कॉमन समस्याएं हैं, जो सारे देशों को परेशान करती हैं चाहे वे हेल्थ की हों, तकनीक की हों, इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की हों, क्लाइमेट चेंज की हों या रीजनल गवर्नमेंट की हों, उनसे निपटने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे चार बड़े देश किस तरह से योगदान दे सकते हैं। चीन इसी से घबरारा हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर यह अजेंडा काम कर जाता है तो वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाशिये पर चला जाएगा। इसलिए वह बेचैन है।

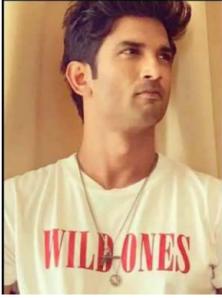
सवाल है कि यूक्रेन में जो हो रहा है, उसका प्रभाव हिंद-प्रशांत में होगा? मुझे लगता है कि यह अपने आप में बड़ा डिवेलपमेंट है और जिस तरह से रूस के साथ चीन खड़ा है, उसे देखते हुए बाकी देशों के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर भारत के लिए। भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं और भारत ने अभी तक यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी नहीं की है। अगर रूस चीन के करीब चला जाता है और रूस पर लगे प्रतिबंधों पर उसे चीन से मदद मिलती है, तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। जूनियर पार्टनर रूस ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं, जिनके अनुसार रूस ने चीन से सैन्य और अर्थव्यवस्था को लेकर मदद मांगी है। अगर चीन इसे मान लेता है तो रूस उसका जूनियर पार्टनर बन जाएगा। चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारत की रक्षा क्षेत्र



को लेकर रूस पर जो निर्भरता है, उस पर क्या असर पड़ेगा? भारत को कूटनीतिक स्तर पर इसका जवाब तलाशना होगा। असल में, चीन ने हिंद-प्रशांत में अमेरिका की तुलना यूरोप के नैटो एक्सपेंशन से करके यह दिखा दिया है कि वह यहां अपना दबदबा कायम करने की नीति पर आगे बढ़ता रहेगा। इसका अर्थ यह भी है कि जैसे-जैसे अमेरिका हिंद-प्रशांत में आगे बढ़ेगा, चीन उसे टारगेट करेगा। यह भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। हमारा पहले से ही उसके साथ विवाद चल रहा है। हिमालय में हमारी फौजें आमने-सामने खड़ी हैं।

## नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग, दिशा सालियान के पेरेंट्स ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

मुंबई: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के माता-पिता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत के बारे में झूठी खबरें फैलाने और परिवार को बदनाम करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उनके बेटे तथा विधायक नितेश और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिशा के पिता सतीश सालियान और मां वसंती ने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। राष्ट्रपति को पत्र सतीश और वसंती



सालियान ने बुधवार को राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर भाजपा नेता राणे और उनके बेटे द्वारा किये जा रहे उपीड़न को रोकने का आग्रह किया।

राणे और उनके बेटे नितेश के खिलाफ दिशा के बारे में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने और गलत जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

दिशा सालियान (28) ने 8 जून, 2020 को उपनगरीय मलाड में एक ऊंची इमारत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, इसके छह दिन बाद राजपूत (34) का शव बांद्रा में उनके अपार्टमेंट के कमरे में लटका पाया गया था। पत्र में राष्ट्रपति को सूचित किया कि उनकी बेटी की मृत्यु के बाद, सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ लोगों ने घटना (उसकी कथित आत्महत्या) को राजपूत की मौत से जोड़ना शुरू कर दिया था और समाचार चैनल व सोशल मीडिया पर 'काल्पनिक तथा तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी' फैलानी शुरू कर दी थी।

## कोरोना मुक्त हुई एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, अब नहीं है कोई भी केस

मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी में दो साल पहले कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और अब धारावी कोविड-19 से मुक्त हो चुकी है। यह क्षेत्र एक समय में कोरोना वायरस संक्रमण का 'हॉटस्पॉट' बन गया था और निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद नगर निकाय के लिए चुनौती बना हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहे जाने वाले बेहद घने इलाके धारावी में बृहस्पतिवार को संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। बृह-मुंबई महानगर पालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धारावी में अभी कोविड-19 का कोई भी मरीज उपचाराधीन नहीं है, जी-उत्तर वार्ड के सहायक निकाय आयुक्त किरण दिग्धकर ने कहा कि 2020 में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ है जब धारावी में कोविड का कोई मरीज उपचाराधीन नहीं है। दिग्धकर ने कहा, "आज धारावी सही मायने में कोविड मुक्त हो चुका है।" उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताह से धारावी में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है और उपचाराधीन सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महामारी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति इस समय घर पर पृथक-वास में नहीं है।

## गड़चिरोली: शराब बेचने वालों की खैर नहीं, अब भरना होगा जुर्माना

मुलचेरा (गड़चिरोली)। आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले में शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी तहसील के ग्राम कोठारी में पिछले एक माह से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। गांव की कानून-व्यवस्था भंग हो रही है। गांव में एक बार फिर शराब बंदी करने के लिए अब ग्राम पंचायत ने शराब विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि, अगर गांव में दोबारा शराब की बिक्री हुई तो उन्हें ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही उनके खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। कोठारी गांव में शराब बंदी दल गठित किया गया है। गांव में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले आठ वर्ष से गांव में शराब बंदी थी। लेकिन पिछले एक माह से गांव में दोबारा शराब की बिक्री शुरू हुई। गांव में करीब 6 से 7 शराब विक्रेता सक्रिय हैं। उनके द्वारा महुआ समेत देशी व अंगरेजी शराब की बिक्री धड़ल्ले से शुरू है। शराब की बिक्री शुरू होने से अन्य गांवों के शराबी भी अब कोठारी में पहुंचने लगे हैं। शाम होते ही संबंधित शराब विक्रेताओं के घरों में शराबियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है।

## महाराष्ट्र: पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे कक्षा पहली से नौवीं के स्कूल

मुंबई। प्रदेश सरकार ने कक्षा पहली से नौवीं और कक्षा 11 वीं के स्कूलों को पूर्ण क्षमता के साथ खोलने के लिए कहा है। स्कूलों में प्रति दिन 100 प्रतिशत विद्यार्थियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। गुरुवार को सरकार के स्कूलों शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार स्कूलों को अप्रैल महीने में हर शनिवार को पूरे समय तक स्कूल शुरू रखना पड़ेगा। जबकि रविवार को ऐच्छिक रूप में स्कूल शुरू रखा जा सकेगा। सरकार ने राज्य के स्कूलों को कक्षा 1 वीं से 9 वीं तक तथा कक्षा 11 वीं की परीक्षा अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में आयोजित करने के लिए कहा है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम मई महीने में घोषित करना होगा।

## नांदूरा: आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मदद का हाथ

नांदूरा. नाम फाउंडेशन यह किसान परिवार के दुःख में आधार देने वाली एवं वे अकेले नहीं, यह विश्वास देने वाली संस्था है, ऐसा प्रतिपादन मंगेश भारसाकले विदग्ध खानदेश के समन्वयक ने किया, हरिश इथापे के मार्गदर्शन में मदद के हर परिवार को 25 हजार का धनादेश दिया गया, कुल 2 लाख 25 हजार रुपए के धनादेश का वितरण उक्त किसान परिवार को किया गया। नाम फाउंडेशन विदग्ध खानदेश प्रमुख हरिश इथापे के मार्गदर्शन में मंगेश भारसाकले ने सानुग्रह राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया था। नांदूरा स्थानीय ओम साई सामाजिक संस्था कार्यालय यहां आयोजित इस कार्यक्रम में नाम द्वारा पहले चरण में बुलढाणा जिले के मलकापुर एवं मोताला तहसील के कुल नौ आत्महत्या ग्रस्त किसान परिवार को प्रत्येकी 25 हजार रुपए का धनादेश दिया गया।

## नाबालिग से छेड़खानी, आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास

अकोला। बार्शिटकली पुलिस थानांतर्गत नाबालिग बालिका को रास्ते में रोक कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दाखिल अपराध में आरोपी निलेश भिमवार हिवराले (35) पर विद्यमान विशेष जिला न्यायाधीश श्री.वी.डी.पिंपलकर के न्यायालय में दोषारोप पत्र रखा गया था। पीडिता के पिता ने 9-8-2014 को इस मामले में शिकायत दी थी। प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से 6 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों के साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 354 अ में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह कैद, धारा 506 (2) के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास 5000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की कैद, पोक्सो कानून की धारा 11-12 में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की कैद की सजा सुनाई। सभी सजाएं आरोपी को एक साथ भुगतनी होगी (अधिकतम सजा 7 साल) जुर्माने की कुल राशि 15000 आरोपी से वसूल होने पर आधी राशि पीडिता व आधी राशि शासन को जमा करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।

## अकोला: विशेष दल का जुआ अड़डे पर छापा, 6 पकड़े

अकोला. तिलक रोड पर स्थित आकार काम्लेक्स के पीछे अलंकार मार्केट में चल रहे वरली मटका व जुआ खेलने वालों पर जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दल ने छापा मारकर 6 लोगों पर कार्रवाई की। विशेष पुलिस दल के प्रमुख विलास पाटील को खुफिया जानकारी मिली कि अलंकार मार्केट परिसर में कुछ लोग पैसों की हारजित पर वरली मटका जुआ खेल रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक पाटील ने अपने दल के साथ मौके पर छापा मारा। इस कार्रवाई में रविंद्र विजय तेलंगडे(48) निवासी पुराना शहर, राजेश जगदीश पाठक (62) निवासी पुराना शहर, विठ्ठल गोपाल सापधारे (30) निवासी हाता अंदूरा, प्रकाश लक्ष्मण बुंदेले (60) निवासी माता नगर, संतोष परशराम जाधव (40) गाथरी नगर, मुख्तार खान बशीर खान (44) निवासी खैर मो. फाट अकोला पुलिस के हत्ये चढ़े।

## परमबीर सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपी मामले की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से दायर मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गौर किया। ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं। ऐसे में उनका मानना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होना उचित है, इसीलिए कोर्ट मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे रही है। परमबीर सिंह मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने परमबीर सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। वहीं सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। वहीं वकील ने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार CBI जांच के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब परमबीर सिंह से जुड़े मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। परमबीर सिंह मामले की होगी CBI जांच मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर मामला सीबीआई



के पास जाए कोर्ट इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी पर बेवजह बोझ क्यों डाला जाए, वहीं सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा था कि परमबीर सिंह कई तक महीने फरार रहता है, सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलने के बाद ही



वह सामने आता है, वकील ने दलील देते कोर्ट से कहा था कि ऐसे व्यक्ति की याचिका पर मामले को स्थानांतरित करना सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मामले पर बहस पूरी होने के बाद सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है।

'CBI जांच में डाली जा रही बाधा' जस्टिस संजय किशन कौल और एम एम सुदेश की बेंच ने आज मामले पर सुनवाई की। परमबीर सिंह के वकील पुनीत बाली ने पक्ष रखते हुए कहा कि एक टेलीफोनिक बातचीत है, जिसे मैंने रिकॉर्ड में रखा है, जहां एक जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहे मामले को वापस ले लो, अपने राजनीतिक आकाओं के साथ मत खेलो। मैंने तुरंत ये बात सीबीआई के सामने रखी और उन्हें बताया कि उनकी जांच में बाधा डाली जा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी है।

### विधायकों से पहले कोरोना योद्धाओं को दें घर", BJP विधायक राम कदम की ठाकरे सरकार को सलाह

महाराष्ट्र में विधायकों से पहले कोविड योद्धाओं को घर देने की मांग उठ रही है. बीजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने ठाकरे सरकार से मांग की है की 300 घर जो मुंबई में सरकार म्हाडा के माध्यम से मुंबई और एमएमआर क्षेत्र के बाहर के विधायकों के लिए बनाने वाली हैं वे घर पहले कोविड में जिन योद्धाओं ने जान गंवाई हैं उन्हें दिए जाए. ऐसी मांग भाजपा विधायक राम कदम ने की है. कदम के अनुसार, "सरकार अपनी प्राथमिकता पहले तय करे और कोविड योद्धा, जिन्होंने अपनी जान लोगों की सेवा करते हुए गंवाई और अब उनके परिवार के पास कोई छत नहीं है ऐसे परिवारों को मुफ्त घर देने चाहिए". कदम ने आगे कहा कि मैं ये भी बातना चाहता हूँ कि हम विधायकों को घर देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पहले घर डॉक्टर, नर्स, बीएमसी स्टाफ जिन्होंने आपनी जान कोविड में गंवाई उन्हें दिये जाए". को गृहनिर्माण के विषय चर्चा करते वक्त मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ये ऐलान किया था कि जो विधायक मुंबई में या फिर एमएमआर क्षेत्र से चुनकर नहीं आए हैं, ऐसे विधायकों के लिए 300 घर म्हाडा बनायगी. ये घर उन्हें खरीदने पड़ेंगे.

## नशे में बहके कदम: मुंबई में शराब पीकर लड़कियों ने कैब पर किया कब्जा, पुलिसकर्मी से की गालीगलौज और धक्कामुक्की



मुंबई में नशे में धुत तीन युवतियों ने बीच सड़क जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इन्होंने ओला कार के ड्राइवर को उसकी कार से बाहर निकाला कार पर कब्जा कर लिया, उसके साथ गालीगलौज की और कार में तोड़फोड़ का प्रयास किया। यही नहीं इन्होंने मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी संग बदसलुकी भी की है। इस मामले में तीनों के खिलाफ नशे में धुत होकर हंगामा करने का केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।

**ओला ड्राइवर ने बनाया घटना का वीडियो**  
इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसे ओला के ड्राइवर ने खुद तैयार किया है। इसी वीडियो के आधार पर तीनों पर कार्रवाई हुई है। वीडियो के आखिर में एक युवती सड़क पर पुलिसकर्मी को गालियां देती नजर आ रही है। हालांकि, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए युवती को समझाता हुआ नजर आ रहा है।

**पहले भी सामने आये हैं ऐसे ही कई मामले**  
पहले भी इस तरह के उल्लंघन के कई मामले मुंबई में सामने आ चुके हैं। शराब पीकर सड़कों पर झगड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी मुंबई पुलिस की ओर से की जाती रही है। अब देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है?

## मुफ्त में शो करो वरना होगी तोड़फोड़! BMC कमिश्नर के भाई की सिंगर सोनू निगम को धमकी, बीजेपी विधायक का दावा

मुंबई: महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अमित साटम ने विधानसभा में दावा किया कि गायक सोनू निगम ने शिकायत की है कि बृह-मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त आई एस चहल के एक 'रिश्तेदार' ने उनसे निःशुल्क शो आयोजित करने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा तथा तोड़फोड़ की गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा। विपक्षी दल के विधायक ने राज्य सरकार से मामले में कार्रवाई की मांग की है। साटम ने विधानसभा में कहा, 'सोनू निगम ने शिकायत दी है



कि चहल के भाई राजिंदर, सोनू निगम को निःशुल्क शो आयोजित करने को कह रहे हैं। ऐसा करने पर

इस पर ध्यान देना चाहिए और राजिंदर और इकबाल सिंह चहल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विधानभवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा विधायक ने आरोप को दोहराया। उन्होंने कहा, 'आई एस चहल के चचेरे भाई राजिंदर ने सोनू निगम से कुछ शो मुफ्त में करने का अनुरोध किया। लेकिन गायक ने मना किया तो उन्हें फोन पर अपशब्द कहे गये और धमकाया गया।' फिलहाल बीएमसी कमिश्नर के ऊपर सरकार कोई कार्रवाई करेगी या नहीं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

उन्के घर नोटिस भेजा जाएगा और तोड़फोड़ की गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा। इसलिए, सरकार को

## मां को पीतते देख बेटे ने पिता के सिर पर किया थपौड़े से वार, मौके पर ही मौत

मुंबई की एक चॉल में रहने वाले 16 वर्षीय बच्चे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग का पति अक्सर शराब के नशे में उसकी मां के साथ मारपीट किया करता था. पुलिस ने कहा कि एक 46 वर्षीय व्यक्ति की उसके 16 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी, जब युवक ने नशे में धुत व्यक्ति को अपनी मां के साथ मारपीट करते देखा था. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 45 वर्षीय महिला, जो मामले में शिकायतकर्ता है, ने पुलिस को बताया कि हत्या कई वर्षों से अपने दो बेटों के सामने अपने पति के हाथों बार-बार किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम है. पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार की रात करीब साढ़े आठ बजे उनके किराए के आवास पर हुई, उन्होंने कहा कि युवक जब घर लौटा तो उसने अपनी मां को पिता द्वारा प्रताड़ित होते देखा. महिला ने अधिकारियों को बताया कि उसके पति ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली थी और उसका सिर दीवार पर पटक रहा था. प्राथमिकी के अनुसार, युवक ने मारपीट को रोकने की कोशिश की लेकिन उसके पिता ने उसे धक्का दे दिया और महिला को पीटना जारी रखा. इसके बाद नाबालिग ने हथौड़ा उठाया और पिता के सिर पर वार कर दिया. वह आदमी फर्श पर गिर गया और चाकू उठाने की कोशिश की. हालांकि, युवक ने पिता के हाथ से चाकू छीन लिया और उसकी गर्दन पर वार कर दिया. यह देख मां फर्श पर गिर पड़ी.

## शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक पर ED की कार्रवाई, अटैच की 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी

प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में 5,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक की 11.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. उन्होंने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में ठाणे, महाराष्ट्र में दो फ्लैट और एक जमीन शामिल है. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि NSEL के डिफॉल्टर्स में से एक आस्था ग्रुप ने 2012-2013 के बीच विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट एलएपीपी को 21.74

करोड़ रुपये डायवर्ट किए. इसमें से 11.35 करोड़ रुपये विहंग एंटरप्राइजेज और विहंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए, जिसका नियंत्रण सरनाईक और उनके परिवार के पास है. आस्था समूह पर एनएसईएल का 242.66 करोड़ रुपये बकाया है. ईडी ने एक बयान में कहा, "मनी ट्रेल, जांच और पहचान के आधार पर, ठाणे, महाराष्ट्र में 2 फ्लैटों और भूमि के एक टुकड़े की संपत्ति कुल रु. 11.35



करोड़ को पीएमएलए 2002 के तहत प्रताप सरनाईक के थे, जो अनंतिम रूप

से कुर्क किया गया है. एजेंसी ने कहा कि शेष 10.50 करोड़ रुपये आस्था समूह से प्राप्त हुए, योगेश देशमुख नाम के एक व्यक्ति को भुगतान किया गया था और धन पहले ही ईडी द्वारा संलग्न किया जा चुका है. इससे पहले इस मामले में 3,242.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य अब 3,254.02 करोड़ रुपये है. ईडी की जांच एनएसईएल के खिलाफ 2013 में मुंबई पुलिस की

आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एक मामले पर आधारित है. ईडी ने कहा, "इस मामले में, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक धन पहले ही ईडी द्वारा संलग्न किया जा चुका है. इससे पहले इस मामले में 3,242.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य अब 3,254.02 करोड़ रुपये है. ईडी की जांच एनएसईएल के खिलाफ 2013 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एक मामले पर आधारित है. ईडी ने कहा, "इस मामले में, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक धन पहले ही ईडी द्वारा संलग्न किया जा चुका है. इससे पहले इस मामले में 3,242.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य अब 3,254.02 करोड़ रुपये है. ईडी की जांच एनएसईएल के खिलाफ 2013 में मुंबई पुलिस की







## खेल जगत



### 24 साल बाद कंगारुओं की पाकिस्तान में जीत: तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 115 रन से हराकर सीरीज जीती, पैट कमिंस बने मैच ऑफ द मैच

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर-1 ऑस्ट्रेलिया



24 साल बाद पाकिस्तान के वॉर पर गई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लाहौर में खेले गए तीसरे टेस्ट को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 115 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान के सामने 351 रन का टारगेट था। जवाब में मेजबान टीम 235 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफ स्पिनर नेथन लायन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके और कप्तान पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए। कैमरन ग्रीन और मिचेल स्टार्क को 1-1 विकेट मिला। मैच में 8 विकेट लेने वाले कप्तान पैट कमिंस को मैच ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं, मैच ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड उस्मान ख्वाजा के खाते में गया। दूसरी पारी में पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक (70) टॉप स्कोरर रहे। उनके अलावा कप्तान बाबर आजम ने 55 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम बेजान

पिचों पर मेजबान टीम को चुनौती देने में सफल रही। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत से 3 विकेट दूर रह गई थी, लेकिन लाहौर में कंगारु टीम ने जीत दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर वन पर पहुंच गई है। वहीं, टीम इंडिया अब तीसरे नंबर पर है। ख्वाजा की शानदार बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में इस खिलाड़ी ने 91 रन और दूसरी पारी में 104 रन बनाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 391 और दूसरी पारी में 227/3 का स्कोर खड़ा किया था। पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 268 रन बनाकर ढेर हो गई और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 123 रन की बढ़त हासिल करने में सफल रही। पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों

ने कहर बरपाते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पिच पर जमने ही नहीं दिया। दूसरी पारी में नाथन लायन ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके। वहीं, पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले कप्तान पैट कमिंस 3 और

मिचेल स्टार्क 1 विकेट ले सके। कैमरून ग्रीन को भी एक सफलता मिली।

### कैप्टन बनने के बाद जडेजा का फर्स्ट रिप्लेसमेंट-बोले-कैप्टेसी की टेंशन नहीं, माही मैदान पर रहेंगे, पहले भी उनके पास जाता था और आगे भी जाऊंगा

इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने से दो दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने रवींद्र

जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंपी है। जडेजा के कप्तान



बनने के बाद उनका पहला रिप्लेसमेंट आया है। उन्होंने कहा, मैं कप्तानी को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि धोनी मेरे साथ खड़े हैं। मुझे उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे मन में अगर किसी तरह का कोई सवाल रहता है तो मैं धोनी के पास ही जाता था और जाता रहूंगा। जडेजा ने आगे कहा- मैं कप्तानी मिलने से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धोनी ने जो विरासत छोड़ी है, उसे मुझे आगे बढ़ाना है। भरोसा जताने के लिए सबका शुक्रिया। सीईओ बोले- धोनी का फैसला टीम हित में वहीं धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद CSK की ओर से जारी बयान में सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा- धोनी के कप्तानी छोड़ने से मैं हैरान हूँ, लेकिन धोनी के फैसले का स्वागत करता हूँ। धोनी ने जो भी फैसला किया है, वह टीम के हित में ही होगा। वह अभी टीम के लिए आगे भी खेलते रहेंगे और उनका मार्गदर्शन टीम को मिलता रहेगा। वह टीम के मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक बने रहेंगे। धोनी ने की थी जडेजा की सिफारिश बयान में आगे कहा गया है कि धोनी ने ही कप्तानी छोड़ने के बाद जडेजा के नाम की सिफारिश की थी।

### IPL का 15वां सीजन, महिला IPL कब होगा शुरू?: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की लीग में खेलती हैं भारतीय क्रिकेटर, पाक-बांग्लादेश न निकल जाएं हमसे आगे

IPL का 15वां सीजन शुरू होने में एक दिन बाकी है। दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड में चल रहे वीमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेटरों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स तक अपनी चमक बिखेरी। भारतीय टीम वुमन वर्ल्ड कप 2017 की उप-विजेता रही, लेकिन देशवासियों के लिए वे विजेता से कम नहीं थीं। 2005 के बाद दूसरा मौका था, जब भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप में उप-विजेता बनी।

देश में क्रिकेट और क्रिकेटर्स को नए मुकाम तक पहुंचाने और नए खिलाड़ियों की पौध तैयार करने में आईपीएल की अहम भूमिका रही है। इस लीग से कई बेहतरीन खिलाड़ी उभरे, जिन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई। विश्व क्रिकेट में भी भारतीय खिलाड़ियों को खास पहचान मिली। पिछले करीब पांच साल से महिला खिलाड़ियों के लिए आईपीएल की मांग भी हो रही है। हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष शीवर गांगुली ने ऐलान किया कि 2023 से वीमेंस आईपीएल की शुरुआत पर विचार किया जा रहा है। मुंबई में गवर्निंग काउंसिल की बैठक में महिला के लिए आईपीएल पर शुक्रवार यानी आज चर्चा होगी।

जब एक हार ने किया चमत्कार 23 जुलाई, 2017 से पहले क्रिकेट

प्रशंसकों का प्रेम टीम इंडिया कही जाने वाली पुरुष टीम को ही मिलता था, लेकिन इसी दिन भारतीय महिला क्रिकेटरों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स तक अपनी चमक बिखेरी। भारतीय टीम वुमन वर्ल्ड कप 2017 की उप-विजेता रही, लेकिन देशवासियों के लिए वे विजेता से कम नहीं थीं। 2005 के बाद दूसरा मौका था, जब भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप में उप-विजेता बनी।

2017 के बाद से बदल गई दुनिया इससे पहले महिला क्रिकेट के मैचों का प्रसारण टीवी पर नहीं किया जाता था। इसके पीछे दलील थी कि महिला टीम में न तो पुरुष टीम जैसे बड़े नाम हैं और न ही प्रायोजकों की लंबी कतारें। 2017 के बाद से महिला क्रिकेट टीम को तवज्जो मिलना शुरू हो गई। मैच टीवी पर लाइव आने लगे। मीडिया में अच्छी खासी कवरेज होने लगी। पुरुष टीम की तरह इस टीम को सपोर्ट भी मिलने लगा। वरिष्ठ खेल पत्रकार मुकेश थपलियाल कहते हैं कि लोहा कमेटी के गठन के बाद से महिला क्रिकेट टीम पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। धरेलू स्तर पर सुधार हुआ महिला खिलाड़ियों को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे और उनके पैसे बढ़ाए गए। रिंकॉर्ड बने तो टीवी पर



प्रसारण होने लगा, सोशल मीडिया पर लोग महिला टीम के फोटो शेयर करने लगे। लोग महिला खिलाड़ियों को पहचानने लगे। इसके बाद ही महिलाओं के लिए इंडियन प्रीमियर लीग बनाने की मांग शुरू हो गई।

महिला खिलाड़ियों की संख्या गिनी-चुनी क्यों?

थपलियाल के मुताबिक, देश में बहुत सी लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। साल 2017 के बाद से परिवार भी अपनी बेटियों का सपोर्ट करने लगे हैं। शहरी लड़कियों के पास तो फैसिलिटी है, लेकिन गांव की लड़कियों के पास ढेरों चुनौतियां हैं। मां-बाप नौकरी हुआ महिला खिलाड़ियों को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे और उनके पैसे बढ़ाए गए। रिंकॉर्ड बने तो टीवी पर

इन देशों में है धरेलू लीग, पाकिस्तान-बांग्लादेश में जल्द होगी शुरु

ऑस्ट्रेलिया में साल 2015 से ही पुरुषों के लीग के साथ-साथ महिलाओं के लिए वुमन्स बिग बैश लीग का भी आयोजन होता है। खास बात यह है कि महिलाओं की इन आठों टीमों का नाम पुरुषों की लीग पर ही है। सिडनी सिक्सर्स की टीम पिछले तीन बार से लगातार खिताब जीत रही है। साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में आठ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने यहां पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए वुमन-100 लीग शुरू कर दी। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी अपने यहां महिला खिलाड़ियों के लिए धरेलू लीग शुरू करने का ऐलान किया है।



## देश परदेश

### सियासत में फौज का दखल: पाकिस्तान आर्मी देश में मिलीजुली सरकार चाहती है, इमरान को विपक्षी नेताओं की शक्ति से भी नफरत

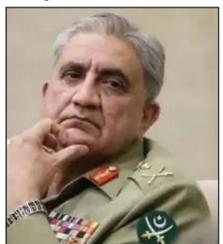


पाकिस्तान की संसद में आज यह तय होगा कि इमरान सरकार के खिलाफ लागू हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कब होगी। संविधान के मुताबिक, अविश्वास प्रस्ताव लागू होने के 3 दिन बाद और 7 दिन अंदर वोटिंग कराना जरूरी है। स्पीकर असद कैसर इमरान के इशारे पर वोटिंग टालना चाहते हैं, जबकि विपक्ष को जीत सामने नजर आ रही है, इसलिए वो इस पर जल्द से जल्द फैसला चाहता है। इस सियासी कवायद में ताकतवर फौज को कथित तौर पर न्यूट्रल बताया जा रहा था, लेकिन अब खबर है कि मुल्क की बदहाल इकोनॉमी और बिगड़ते हालात को देखते हुए फौज चाहती है कि देश में सभी पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनाई जाए। हालांकि, इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं बताए जाते। फौज क्या सोच रही है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ने फौज के इरादों की जानकारी है। अब्बासी को सेना का करीबी माना जाता है। दरअसल, चंद्र दिन पहले 'द जंग' अखबार में

अब्बासी का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था- मुल्क इस वक्त बेहद मुश्किल हालात में है। सियासतदान मुल्क की बेहद बुराई के बजाए सिर्फ खुद पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे वक्त फौज को दखल देना चाहिए। बरना इन हालात में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाए। मुल्क की सलामती फौज के हाथों में है। जनरल ने क्रिया फोन

अब्बासी ने सोशल मीडिया पर कहा- आर्टिकल के बाद फौज के एक आला जनरल ने मुझे फोन किया। उन्होंने पूछा- आपको क्या लगता है कि फौज को क्या करना चाहिए? मैंने कहा- हमारी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। हर दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। फरिन पॉलिसी जैसी कोई चीज नहीं दिखती। इसलिए फौज को सियासत में दखल देना चाहिए। फौज ने पहले भी इन हालात को संभाला है। अब्बासी कहते हैं- कुछ दिन बाद मेरे पास उसी जनरल का फोन दोबारा आया। इस दफा उन्होंने

कहा- हम हुकूमत से नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अपोजिशन के नेता रैलियों और मार्च निकालने में व्यस्त हैं, लेकिन हमने अपना मेसेज उन तक पहुंचा दिया है। अब देखते हैं कि उनका स्टैंड इस बारे में क्या रहता है। कामयाबी की गुंजाइश बहुत कम फौज भले ही मिलीजुली सरकार के लिए कोशिश कर रही हो, लेकिन इसका साकार होना तकरीबन नामुमकिन जैसा ही है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कह चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल-उर-रहमान से हाथ मिलाता तो दूर उनके बगल में खड़ा होना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। दूसरी तरफ, विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि अगर फौज ने इमरान का साथ नहीं दिया और वो न्यूट्रल रही (जैसा नजर आ रहा है) तो इमरान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर करारी शिकस्त मिलना तय है। लिहाजा, ये कहा जा सकता है कि मिलीजुली सरकार बनना बेहद मुश्किल है।



### रूस के हर कदम पर अमेरिका की नजर: पुतिन के केमिकल वॉर प्लान को लेकर अमेरिका चौकस, बाइडेन की सीक्रेट टाइगर टीम रख रही नजर

यूक्रेन पर हमले के एक माह बीत जाने के बाद भी रूस निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब केमिकल हमले का प्लान बनाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन, यूक्रेन के कुछ शहरों में केमिकल हमले या फिर बायोलांजिकल हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका ने इस आशंका के चलते सीक्रेट टाइगर टीम का गठन किया है। इस टीम में अमेरिका के शीर्ष 20 सैन्य अफसरों को शामिल किया गया है। ये टीम हर सप्ताह में तीन बार

बैठक करती है। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड सहित अन्य नाटो देशों से ये टीम लगातार खुफिया इनपुट के आधार पर रूसी सेना की कार्रवाई पर नजर रख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूसी सेनाओं की बेहद धीमी बढ़त, अब तक लगभग 7 हजार सैनिकों सहित 20 टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद पुतिन काफी बेचैन हैं। ब्रसेल्स में नाटो की बैठक में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भी आशंका जताई कि रूस, यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। हमारे हांसले बुलंद, रूस अपने मंसूबों में विफल होगा।



जेलेंस्की नाटो की बैठक में अपने वचुअल संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमारे हांसले बुलंद हैं। रूसी मंसूबे नाकाम होंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो

बाइडेन ने ब्रसेल्स में नाटो की बैठक में ऐलान किया कि अमेरिका आने वाले दिनों में यूक्रेन के लगभग एक लाख शरणार्थियों अपने यहां जगह देगा। पुतिन के सलाहकार अनातोली चुबैस का इस्तीफा, देश छोड़ा पुतिन के प्रमुख सलाहकार अनातोली चुबैस ने बुधवार को यूक्रेन हमले के विरोध में इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। वे युद्ध की शुरुआत से ही इसके खिलाफ लिख रहे हैं। उन्होंने मारे गए राजनेता बोरिस नेमत्सोव और उदारवादी अर्थशास्त्री येगोर गेदर की तस्वीरें पोस्ट की। रूसी सुरक्षा परिषद के

उपाध्यक्ष इवोरकोविच ने भी एक इंटरव्यू में युद्ध की निंदा की थी। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। रूसी कब्जे वाले खेर्सोन के सिटी हॉल में लहराया यूक्रेन का ध्वज रूसी कब्जे वाले खेर्सोन शहर छोड़ा पुतिन के प्रमुख सलाहकार अनातोली चुबैस ने बुधवार को यूक्रेन हमले के विरोध में इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। वे युद्ध की शुरुआत से ही इसके खिलाफ लिख रहे हैं। उन्होंने मारे गए राजनेता बोरिस नेमत्सोव और उदारवादी अर्थशास्त्री येगोर गेदर की तस्वीरें पोस्ट की। रूसी सुरक्षा परिषद के

### रूसी सेना पर किडनेप कर बंधक बनाने का आरोप: कई पत्रकारों समेत रूस के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग निशाने पर, टॉर्चर कर रहे सैनिक

यूक्रेन पर रूस का हमला तेज होता जा रहा है। इस हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। इस बीच UN ने कहा है कि रूसी सैनिक लोगों का अपहरण कर रहे हैं। इससे लोगों के मन में डर बैठ गया है। UN ने कहा- लोगों को पकड़कर उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। ऐसे कम से कम 36 मामले दर्ज किए गए हैं। इन लोगों का परिवार नहीं जानता कि रूसी सैनिक उन्हें क्यों ले गए हैं। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पत्रकार को किडनेप किया 15 मार्च को पूर्व और दक्षिण में रूसी आक्रमण को कवर करने

वाली यूक्रेन की एक पत्रकार विक्टोरिया रोशचिना का अपहरण कर लिया गया। न्यूज इंस्टीट्यूट 'होरोमाडस्के' ने अपने बयान में आरोप लगाया कि रूस की संधीय सुरक्षा सेवा (FSB) और रूसी सेना ने दक्षिणपूर्वी जापोरिजिया क्षेत्र के बंदरगाह शहर बर्दियांसक में उनकी पत्रकार का अपहरण कर लिया। यूक्रेन के नेशनल यूनिशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (NUJ) ने कहा कि चार अन्य पत्रकारों को भी मेलिटोपोल में बंधक बनाया गया है। एक पिता को बंधक बनाया कब्जे वाले शहर मेलिटोपोल में एक पत्रकार स्वेतलाना जालिजेत्सकाया ने रूसी सेना पर उसके 75 साल के पिता को बंधक बनाने का आरोप लगाया है।

पत्रकार ने कहा कि उसने रूसी प्रशासन के साथ को-ऑपरेट करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे सजा देने के लिए पिता को बंधक बना लिया गया। लोकल न्यूज एजेंसी RIA मेलिटोपोल की पत्रकार जालिजेत्सकाया ने फेसबुक पर लिखा कि शहर में मौजूद एक रूसी नेता के साथ उनकी मुलाकात के बाद उनके पिता को बंधक बना लिया गया। मुलाकात के दौरान उन्होंने हमले की आलोचना की थी और इस कदम को गलत बताया था। रूस के खिलाफ आवाज उठाने पर निशाना UN के एक स्पोकसपर्सन ने बताया कि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वे ज्यादातर स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि हैं।



इनमें पत्रकार भी शामिल हैं। साथ ही उन लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो रूस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन लोगों की सूची रूसी अधिकारियों ने बनाई थी, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है या नहीं। दरअसल, अमेरिका ने फरवरी में संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में दावा किया गया था कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन में कुछ चुनिंदा लोगों को मार देगा। कुछ लोगों को शिविरों में भेजा जाएगा। इन सब के नामों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों में कई अधिकारियों को भी रूसी सेना ने बंधक बनाया है। उत्तर के नोवा काखोवका के सचिव को अगवा कर लिया गया।





## नाटा 2022: आर्किटेक्चर प्रोग्राम का प्रवेश द्वार



**आर्किटेक्चर धीरुग सङ्करा**  
(प्रधान अध्यापक)  
ठाकुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर  
एंड प्लानिंग, मुंबई

वास्तुकला को पेशेवर करियर के सबसे उभरते क्षेत्रों में से एक के रूप में देखा जाता है। आज वास्तुकला, योजना और डिजाइन के क्षेत्र में कुशल तकनीकी पेशेवरों की मांग है। आर्किटेक्चर में (NATA) नेशनल एटीट्यूड टेस्ट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। यदि कोई उम्मीदवार आर्किटेक्चर बनना चाहता है, तो उम्मीदवार को NATA परीक्षा से गुजरना होगा और देश के आर्किटेक्चर कॉलेजों में B.Arch प्रवेश प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। NATA अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र के लिए आवेदक की योग्यता को मापता है, अर्थात् वास्तुकला,

संज्ञानात्मक कौशल, दृश्य धारणा और सौंदर्य संवेदनशीलता परीक्षण, तार्किक तर्क और महत्वपूर्ण सोच क्षमता, आदि के मूल्यांकन के माध्यम से, उम्मीदवार ने अतीत में जो सीख हासिल की है, उसके अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है।

NATA 2022 परीक्षा तिथियां जारी कर दी गई हैं। परीक्षा प्राधिकरण तीन सर्तों में NATA



परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। NATA 2022 परीक्षा क्रमशः 12 जून, 3 जुलाई और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी।

नाटा पात्रता मानदंड NATA 2022 परीक्षा के लिए पूर्ण पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

• योग्यता: (NATA) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2

इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

• विषय: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अनिवार्य विषयों में से एक के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

• अंक: परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को पीसीएम विषयों में कम से कम 50% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए।

• पात्रता: 2022 में अंतिम वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण और अपडेट के लिए कृपया [www.nata.in](http://www.nata.in) पर लॉग ऑन करें। परीक्षा के प्राप्ति और आर्किटेक्चर में प्रवेश प्रक्रिया का विवरण एकत्र करने के लिए आप आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में जा सकते हैं।

## मुम्बई में अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता "मिस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल" में 25 देशों की ब्यूटी क्वीन्स लेंगी हिस्सा

ऋषिकेश मिराजकर द्वारा आयोजित यूनिक्स कांटेस्ट का फाइनल 2 अप्रैल को होगा

मायागरी मुम्बई में 2 अप्रैल 2022 को भव्य रूप से अपनी तरह की एक अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता "मिस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल" का फाइनल होने जा रहा है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्यूटी पेजेंट के ऑर्गनाइजर ऋषिकेश मिराजकर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भारत सहित दुनिया भर के 25 देशों की ब्यूटी क्वीन्स हिस्सा लेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बतौर डायरेक्टर कई ब्यूटी पेजेंट्स दूसरों के लिए इंडिया के नाम से मिस इंडिया मुकाबले का आयोजन पिछले 5 वर्षों से करता आ रहा हूँ। इस अनोखे शो मिस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल का आईडिया मुझे उस वक्त आया जब मैंने सोचा कि



अपना खुद का एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करे। यह सिर्फ फैशन से संबंधित इंडस्ट्री ही नहीं है बल्कि सोशल एक्टिविटी भी की जा सकती है। पर्यावरण से जुड़े मामलों, कैसर पेशेंट्स से जुड़ी कोई बात हो, तो इसके द्वारा एक मैसेज देकर लोगों को अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है इसलिए मैंने इसका नाम मिस

एनवायरनमेंट इंटरनेशनल सोचा, क्योंकि यह शब्द अपने अंदर बेशुमार मायने रखता है। इस ब्यूटी पेजेंट का यह पहला साल है। टोटल इस प्रतियोगिता में 20 महिलाएं भाग लेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया जबकि 24 मार्च से बाकी 5 पार्टिसिपेंट्स भी शामिल हो जाएंगी। भारत, यूगांडा, बेलजियम, यूनाइटेड किंगडम सहित कुल 25 देशों की हसीनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। पहले

नेशनल डायरेक्टर को चुनना पड़ता है। हमें नेशनल डायरेक्टर को इवेंट के बारे में पूरी डिटेल्स बतानी पड़ती है। आपको बता दें कि इस सौंदर्य प्रतियोगिता की विनर को 10 लाख का क्राउन मिलने वाला है, साढ़े तीन हजार डॉलर की इनाम राशि है। पूरे साल में इस प्रोजेक्ट के प्रमोशन के सिलसिले में विजेता 4 देशों में घूमेंगी। पहले मारिशियस, फिर जिम्बाब्वे, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम फिर एक बार और इन्हें

इंडिया लाया जाएगा। मेमोरी मेकर्स इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत यह ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। यह कंपनी फैशन इवेंट के लिए प्रसिद्ध है और इनका पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा। श्रीमती रेखा विजय मिराजकर भी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। उनका सम्बन्ध फैशन वर्ल्ड से रहा है, स्टेज के बारे में उन्हें काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। ऋषिकेश ने आगे कहा कि देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ठाणे महानगरपालिका ने मुंबई में इस तरह के ग्रैंड इवेंट को करवाने में काफी सहयोग दिया है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने सारे देशों की महिलाओं को वीजा मिलना आसान नहीं होता जबकि कोविड 19 के हालात हैं मगर सभी के सहयोग से यह संभव हो पाया है।

## मोदी Vs केजरीवाल: भाजपा के यूपी मॉडल और आप के पंजाब मॉडल में होगी लड़ाई, कौन जीतेगा जनता का दिल?



योगी आदित्यनाथ ने अपने 51 मंत्रियों के साथ शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण किया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में समाज के सभी क्षेत्रों, वर्गों के लोगों को शामिल कर भाजपा ने एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल में बेहद सामान्य परिवारों से आए कार्यकर्ताओं को भी शामिल कर पार्टी के गरीबों के साथ खड़ा होने का संकेत भी दिया गया है। इसे उसकी 2024 की लड़ाई की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

इसके पहले भगवंत मान के मंत्रिमंडल की खूब चर्चा हुई थी। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के मंत्रिमंडल में ऐसे सामान्य चेहरों को जगह दी है, जो बेहद निम्न तबकों से आते हैं। पढ़े-लिखे और योग्य लोगों को साथ लेकर पार्टी ने जहां यह संकेत देने की कोशिश की थी कि वह एक बेहतर सरकार चलाने के लिए तैयार है तो वहीं सामान्य चेहरों के जरिए मंत्रिमंडल में गरीब लोगों की भागीदारी को भी दिखाए की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी को आने वाले दिनों में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच कई राज्यों में मजबूत लड़ाई हो सकती है। इसे

देखते हुए दोनों ही दल अपनी कमर कसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी इन सरकारों को एक मॉडल के रूप में पेश कर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर सकती हैं।

भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के सहारे बेहतर कामकाज और जनहितैषी योजनाओं का एक मॉडल पेश करने की कोशिश करेगी, तो अरविंद केजरीवाल मान सरकार के सहारे शिक्षा-स्वास्थ्य के राजनीति की एक नई पारी खेलने की कोशिश करेगा। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों को आम गरीबों के साथ जोड़कर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करेगा। प्रचार तंत्र में माहिर खिलाड़ी राजनीति की लड़ाई को परसेप्शन का खेल माना जाता है। जनता के मन में परसेप्शन बनाने के खेल में मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपनी उपलब्धियों को बेहतर ढंग के साथ पेश करने के साथ ही विपक्ष पर हमला करना भी शामिल माना जाता है। इससे ही जनता के बीच किसी पार्टी या सरकार को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक छवि बनती है।

## अनधिकृत टिकट दलालों के विरुद्ध पश्चिम रेलवे की बड़ी कार्यवाही



गणेश पाण्डेय। मुंबई रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक ने पश्चिम रेलवे के रेल सुरक्षा बल के प्रयासों को सराहा। 2.18 करोड़ रु. मूल्य के ई-टिकटों के साथ-साथ यात्रा-सह-आरक्षण टिकट भी जब्त किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे बोर्ड श्री संजय चंद्र ने दलालों के खिलाफ इन विशेष अभियानों से आरपीएफ पश्चिम रेलवे द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय परिणामों की सराहना की है। अपने प्रशंसा पत्र में चंद्र ने यह भी उल्लेख किया कि इस तरह के अभियानों के सफल निष्पादन से रेलवे प्रणाली में आम जनता का विश्वास बढ़ता है। उन्होंने पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम को उनके प्रयास जारी रखने और भविष्य में भी ऐसे निरंतर अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकार द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक पश्चिम रेलवे के रेल सुरक्षा बल द्वारा

दलालों के खिलाफ विशेष अभियान के लिए आरपीएफ अपराध शाखा, साइबर सेल और मंडलों के डिटेक्टिव विंग से समर्पित कर्मचारियों की विशेष टीमों का गठन किया। यह देखा गया कि दलाल कई फर्जी पहचान पत्रों का उपयोग करके टिकट बुक कर रहे थे, जिनमें कुछ अधिकृत आईआरसीटीसी एजेंट भी शामिल थे, जिन्होंने टिकट जारी करने के लिए फर्जी आईडी और अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, जिससे यात्रियों से अतिरिक्त पैसे वसूल किए जा रहे थे। 2021 में पश्चिम रेलवे के रेल सुरक्षा बल ने दलाली के 684 मामलों में 824 लोगों को गिरफ्तार किया और 2.18 करोड़ रु. मूल्य के कुल 19,268 टिकटों को जब्त किया। दलालों की गिरफ्तारी और अभियोजन के लिए इस तरह के निचयित अभियानों के अलावा पश्चिम रेलवे के रेल सुरक्षा बल ने अवैध दलालों के माध्यम से टिकट खरीदने से रोकने के लिए जनता को जागरूक करने हेतु कई जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य यात्रियों को रेलवे अधिनियम की धारा 143 के कानूनी प्रावधानों और दलालों से टिकट/ई-टिकट खरीदने के परिणामों के बारे में शिक्षित करना भी है।

## आरपीएफ अंधेरी नेस्टेशन पर मोबाइल चोरपकड़ा

संवाददाता। मुंबई पश्चिम रेलवे के रेल सुरक्षा बल (RPF) के जवान यात्रियों के साथ-साथ उनके सामान की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गहन निगरानी के एक और उदाहरण में पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम ने अंधेरी स्टेशन पर सीसीटीवी निगरानी की मदद से एक आदतन चोर को पकड़ा। रेलवे अधिकारी अनुसार हाल ही में अंधेरी पोस्ट के रेल सुरक्षा बल के अपराध निवारण जांच दल (CPDS) ने अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 और 7 पर एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा। सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए उस पर पैनी नजर रखी जा रही थी। संदिग्ध व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे एक यात्री की जेब से सैमसंग मोबाइल (10,000 रुपये मूल्य का) की चोरी कर भागने की कोशिश की किंतु अपराध निवारण जांच दल की सतर्कता से उसे तुरंत पकड़ लिया गया तथा आरपीएफ पोस्ट लाया गया, जहां उसने अपना नाम जाहिर शोख, निवासी अंधेरी पूर्व, साकीनाका बताया। उसने 13 मार्च, 2022 को एक अन्य यात्री के मोबाइल चोरी के मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बरामद की गई चोरी की संपत्ति के साथ आरोपी को उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी/अंधेरी को सौंप दिया गया, जहां उसके खिलाफ आईपीसी 379 के अंतर्गत जीआरपी/अंधेरी/सीआर 12/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह भी पता चला कि आरोपी आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में चोरी, डकैती और एनडीपीएस एक्ट सहित आईपीसी के तहत 12 अन्य मामले दर्ज थे।



## राज्यपाल, ईडी केवल महाराष्ट्र प. बंगाल सरकार को टारगेट कर रहे हैं - संजय राऊत



नागपुरा राज्यपाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केवल महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को टारगेट कर रहे हैं। भाजपा शासित प्रदेशों में भी राज्यपाल और ईडी के कार्यालय हैं लेकिन उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है। इस तरह का आरोप शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत ने लगाया है। शिवसंपर्क अभियान के निमित्त नागपुर में शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत ने गुस्वारा को पत्रकारों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृहविभाग की एक आदर्श परंपरा रही है। वह कभी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरह देश की भावना से व्यवहार नहीं करता है। सांसद राऊत से पत्रकारों ने सवाल किया कि कर्नाटक के उडुपी में आयोजित एक वार्षिक समारोह में हिंदूवादी संगठन के माध्यम से गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने दी गई। इसका जवाब देते हुए उन्होंने इस तरह के कृत्यों के चलते देश के बंटवारे के पहले की स्थिति पैदा होने की संभावना जताई। सांसद राऊत ने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विदर्भ के एक शिवसेना विधायक को मंत्रिमंडल में समावेश करने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही निर्णय लेंगे।

नागपुरा राज्यपाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केवल महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को टारगेट कर रहे हैं। भाजपा शासित प्रदेशों में भी राज्यपाल और ईडी के कार्यालय हैं लेकिन उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है। इस तरह का आरोप शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत ने लगाया है। शिवसंपर्क अभियान के निमित्त नागपुर में शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत ने गुस्वारा को पत्रकारों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृहविभाग की एक आदर्श परंपरा रही है। वह कभी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरह देश की भावना से व्यवहार नहीं करता है। सांसद राऊत से पत्रकारों ने सवाल किया कि कर्नाटक के उडुपी में आयोजित एक वार्षिक समारोह में हिंदूवादी संगठन के माध्यम से गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने दी गई। इसका जवाब देते हुए उन्होंने इस तरह के कृत्यों के चलते देश के बंटवारे के पहले की स्थिति पैदा होने की संभावना जताई। सांसद राऊत ने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विदर्भ के एक शिवसेना विधायक को मंत्रिमंडल में समावेश करने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही निर्णय लेंगे।

## महिलाओं एवं बच्चों के अत्याचारियों को जल्द सजा देगी 'अनन्या'... विशेष अदालत बिल विधान परिषद में भी हुआ पास



मुंबई। राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों को रोकने एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार की ओर से लाए गए शक्ति कानून के तहत 'अनन्या' विशेष अदालत विधेयक गुस्वारा को विधान परिषद में भी पारित हो गया। इसी के साथ महिलाओं और बच्चों के साथ जघन्य कृत्यों को अंजाम देनेवालों पर लगाम लगानेवाला शक्ति सुरक्षा

कवच और मजबूत हो गया है। उक्त मामलों को निपटानेवाले विशेष अदालत विधेयक को सर्वसम्मति से सदन में पास किया गया। सदन में उपसभापति नीलम गोहने ने विधेयक पास होने के बाद अभिप्रेत करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे फास्ट ट्रेक अदालत के जरिए महिलाओं एवं बच्चों को कम समय में न्याय मिलेगा।

साथ होनेवाले अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने 'शक्ति' कानून पहले ही पास कराया है। उसी के तहत अब उनसे जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 'अनन्या' विशेष अदालत की स्थापना के लिए कानूनी बदलाव कर यह विधेयक लाया गया है। इससे महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अन्याय और उनके खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगेगा, साथ ही उनसे जुड़े मामले फास्ट ट्रेक पर विशेष अदालत के माध्यम से चलाए जा सकेंगे। महिला सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम उपसभापति नीलम गोहने ने विधेयक पास होने के बाद अभिप्रेत करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे फास्ट ट्रेक अदालत के जरिए महिलाओं एवं बच्चों को कम समय में न्याय मिलेगा।

## मुंबई के विकास में दिल्ली का रोड़ा! केंद्र के कारण लटका धारावी का पुनर्विकास, उद्धव ठाकरे का तीखा आरोप

मुंबई। मुंबई के पुनर्विकास में केंद्र सरकार की ओर से रोड़ा डाला जा रहा है। खासकर धारावी पुनर्विकास परियोजना का काम केंद्र सरकार की वजह से लटका हुआ है। आठ सौ करोड़ रुपये भुगतान करने के बाद भी रेल मंत्रालय जमीन हस्तांतरित करने में ढिलाई बरत रहा है। कई परियोजनाओं को हम गति दे रहे हैं तो कई परियोजनाओं का विचार है, लेकिन उसे हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वह अपने अधीन नहीं बल्कि केंद्र के अधीन है। इन शब्दों में कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीडीडी चाल, एसआरए योजना, ज़रूरतमंदों को घर, म्हाडा सोसायटियों को सेवा शुल्क या अकृषिक टैक्स में राहत और ३०० विधायकों के लिए स्थायी घर बनाने जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी मंत्रियों के काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारी



सरकार बेहतर काम कर रही है। हम जो कहते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं और योजनाओं को पूरा करने की घोषणा और आश्वासन आश्वासन में अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों की ओर से दे रहा हूँ, उन्हें केवल कामजो में सीमित न रखकर प्रस्तावित परियोजनाओं को आकार दिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से डाले जा रहे अड़ों में से धारावी के पुनर्विकास का उदाहरण देते हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि धारावी का विकास होना चाहिए। लेकिन उसका विकास होता नहीं दिख रहा क्योंकि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार से जो बातचीत चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। रेलवे की जमीन हस्तांतरित करने के लिए तकरीबन ८०० करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैंने रेल मंत्री से भी बात की, लेकिन जमीन हस्तांतरण का मसला अभी तक हल नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि केंद्र के अधीन जितनी जमीनें हैं, उसका केंद्र सरकार से लगातार प्रयास करके स्थायी हल निकालना होगा। साहेब ने तैयार की थी एसआरए की संकल्पना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी पार्टियों के विधायकों को स्थायी घर देना चाहते हैं, इसके लिए मुंबई के गोरगांव में ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों के लिए ३०० घर बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि मुंबई में लोगों को रोटी-कपड़ा मिल जाता है, लेकिन मकान नहीं मिलता।